शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 28 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 6 – 13 जुलाई 2026 मूल्य पांच रूपये

क्या युवाओं के मुद्दों पर भाजपा को घेरकर 2027 की सियासी पटकथा लिख रही है कांग्रेस?

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यूथ कांग्रेस के 'छात्रें की गूंज' अभियान की शुरुआत के दौरान जिस तरह NEET पेपर लीक, अग्निवीर योजना, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और शिक्षा सुधार को एक ही मंच से जोड़ा, उससे यह संकेत मिला कि कांग्रेस अब भाजपा के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार 'युवाओं का भविष्य' बनाने की तैयारी में है। यह महज एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीतिक अभियान का उद्घोष था।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में हुए NEET पेपर लीक ने लाखों विद्यार्थियों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। उनका कहना था कि जब देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो जाएं तो यह केवल परीक्षा प्रणाली की विफलता नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था की जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्न है। यह मुद्दा कांग्रेस के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि NEET विवाद ने राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के बीच असंतोष पैदा किया था और विपक्ष लगातार इसे केंद्र सरकार की प्रशासनिक विफलता के रूप में पेश करता रहा है।

लेकिन मुख्यमंत्री का हमला केवल NEET तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अग्निवीर योजना को हिमाचल के युवाओं के साथ 'अन्याय' करार देते हुए कहा कि प्रदेश के हजारों युवाओं का सपना सेना में नियमित भर्ती का होता था, जिसे चार वर्ष की सेवा वाली नई व्यवस्था ने प्रभावित किया है। हिमाचल की सामाजिक और आर्थिक संरचना में सेना का विशेष स्थान रहा है। लगभग हर जिले से बड़ी संख्या में युवा सशस्त्र बलों में भर्ती होते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर भुनाने की कोशिश कर रही है।

दिलचस्प यह भी है कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए हिमाचल में पूर्व भाजपा सरकार के दौरान हुए पुलिस भर्ती और अधीनस्थ चयन आयोग के पेपर लीक मामलों को भी याद दिलाया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने राज्य चयन आयोग का गठन कर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है और नियमित भर्तियों को मेरिट के आधार पर आगे बढ़ाया है। कांग्रेस का प्रयास यह संदेश देने का है कि जहां भाजपा के शासनकाल में भर्ती परीक्षाएं विवादों में रहीं, वहीं वर्तमान सरकार व्यवस्था सुधार का दावा कर रही है। हालांकि भाजपा इन दावों को राजनीतिक प्रचार बताती रही है और कहती है कि रोजगार के मोर्चे पर कांग्रेस अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही है।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में हिमाचल को देश का नंबर एक राज्य बनाने का लक्ष्य भी दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक सुविधाओं वाले सीबीएसई स्कूल स्थापित कर रही है, शिक्षकों की नियुक्तियां की जा रही हैं और शिक्षा की गुणवत्ता में प्रदेश की रैंकिंग में सुधार हुआ है। यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य में स्कूलों के युक्तिकरण, शिक्षकों की कमी और कई सरकारी स्कूलों के विलय या बंद होने को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में किए गए दावे भी आने वाले समय में राजनीतिक बहस का विषय बनने तय हैं।

युवाओं के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, प्राकृतिक खेती, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा ऋण जैसी योजनाओं का उल्लेख कर यह संदेश देने का प्रयास किया कि राज्य सरकार केवल राजनीतिक आरोप नहीं लगा रही, बल्कि समानांतर रूप से विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर भी काम कर रही है। लेकिन भाषण का सबसे राजनीतिक हिस्सा वह था, जब उन्होंने भाजपा पर पुरानी पेंशन योजना का विरोध करने, राज्य के अधिकारों की अनदेखी करने और 2027 में सत्ता परिवर्तन की बात कही। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस अब राष्ट्रीय मुद्दों और राज्य सरकार की योजनाओं को जोड़कर संयुक्त चुनावी नैरेटिव तैयार कर रही है।

यूथ कांग्रेस के 'छात्रों की गूंज' अभियान की घोषणा भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। संगठन ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में धरना-प्रदर्शन कर छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने की घोषणा की है। इसका सीधा अर्थ है कि आने वाले दिनों में NEET, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाएं, अग्निवीर और शिक्षा जैसे विषय प्रदेश की राजनीतिक बहस के केंद्र में रहेंगे। कांग्रेस की कोशिश है कि इन मुद्दों के जरिए वह पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों तक सीधी पहुंच बनाए।

दूसरी ओर भाजपा का तर्क

शेष पृष्ठ 8 पर.....

कांग्रेस सरकार के साढ़े तीन साल के कार्यकाल की बनेगी चार्जशीट:बिंदल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के साढ़े तीन वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक अभियान छेड़ने का ऐलान किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि पार्टी सरकार के कार्यकाल की विस्तृत चार्जशीट तैयार कर गांव-गांव और शहर-शहर जनता के बीच जाएगी। इस चार्जशीट में चुनावी गारंटियों, अधूरे वादों, आर्थिक स्थिति, कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों को शामिल किया जाएगा।

डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने महिलाओं, युवाओं, किसानों, बागवानों, कर्मचारियों और बेरोजगारों से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद अधिकांश गारंटियां अधूरी रह गई। उन्होंने कहा कि अब जनता सरकार से जवाब मांग रही है और भाजपा इन सवालों को जन-जन तक पहुंचाएगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा की चार्जशीट में महिलाओं को आर्थिक सहायता, युवाओं को रोजगार, किसानों और बागवानों से जुड़े वादे, कर्मचारियों को दिए गए आश्वासन, प्रदेश की आर्थिक स्थिति, कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार के आरोप और विकास कार्यों की रफ्तार जैसे सभी प्रमुख मुद्दों को तथ्यात्मक रूप से शामिल किया जाएगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने विकास को गति देने के बजाय जनता पर करों और विभिन्न शुल्कों का बोझ बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि कई विकास परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं और प्रदेश में आर्थिक अनिश्चितता का माहौल बना है। पार्टी इन सभी मुद्दों को प्रमाण सहित जनता के सामने रखेगी।

डॉ. बिंदल ने बताया कि चार्जशीट को केवल एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं, बल्कि सरकार की कथनी और करनी का लेखा-जोखा बनाकर प्रदेशभर में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को सरकार के प्रदर्शन और चुनावी वादों की वास्तविक स्थिति से अवगत कराएंगे।

सरदार पटेल की एकता और संघवाद की सोच देश की ताकत: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल केवल देश के राजनीतिक एकीकरण के शिल्पकार ही नहीं, बल्कि संविधान सभी को एक सूत्र में बांधता है।

राज्यपाल भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी सरदार पटेल की कृष्टि, एकीकरण, एकात्मता और संघवाद की परिकल्पना तथा वंदे मातरम् की यात्रा प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों में राष्ट्रभक्ति और बलिदान की भावना जगाई। यह प्रदर्शनी युवाओं को देश के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने की प्रेरणा देगी।

राज्यपाल ने कहा कि सरदार पटेल ने 560 से अधिक रियासतों का भारत में विलय कर देश की एकता को मजबूत किया। उन्होंने गुजरात में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया।

कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन खराब मौसम के कारण शामिल नहीं हो सके। उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर कई पुस्तकों का विमोचन भी किया गया।

एचएएस एवं संबद्ध सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राज्यपाल से की मुलाकात

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचएएस) और संबद्ध सेवाओं के 2025 बैच के 27 प्रशिक्षु अधिकारियों ने लोक भवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। ये अधिकारी हिप्पा, शिमला में छह सप्ताह के फाउंडेशन कोर्स का प्रशिक्षण ले रहे हैं।

राज्यपाल ने अधिकारियों को चयन के लिए बधाई देते हुए कहा कि प्रशासनिक सेवा केवल नौकरी नहीं, बल्कि जनता की सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी, पारदर्शिता और जनहित को प्राथमिकता देते हुए कार्य करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में दूर-दराज के क्षेत्रों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाना बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही भूस्खलन, बादल फटने और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना जरूरी है।

राज्यपाल ने प्रशासन में ई-गवर्नेंस और आधुनिक तकनीक के अधिक उपयोग पर भी जोर दिया और कहा कि इससे सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेंगी। उन्होंने अधिकारियों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को पूरा करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर हिप्पा की निदेशक रूपाली ठाकुर, राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

विकसित भारत-2047 के लिए स्मार्ट और सतत् शहर जरूरी:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि विकसित भारत-2047 का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब देश के शहर स्मार्ट, समावेशी, पर्यावरण के अनुकूल और नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप विकसित होंगे।

पुणे में आयोजित फ्यूचर सिटीज फोरम-2026को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शहर केवल इमारतों और सड़कों का समूह नहीं हैं, बल्कि आर्थिक विकास, नवाचार और रोजगार के प्रमुख केंद्र हैं।

उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शहरों को आधुनिक तकनीक के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखना होगा। भविष्य के शहर स्वच्छ, सुरक्षित, हरित और सभी वर्गों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने वाले होने चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि बेहतर शहरी विकास के लिए सरकार, स्थानीय निकायों, उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिकों के बीच मजबूत साझेदारी जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि फोरम से मिले सुझाव भविष्य की शहरी विकास नीतियों को नई दिशा देंगे।

एचपीपीटीसीएल ने सुख आश्रय कोष को दिए 95 लाख रुपये

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीटीसीएल) ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत सुख आश्रय कोष के लिए 95 लाख रुपये का योगदान दिया है।

मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू को एचपीपीटीसीएल की ओर से 95 लाख रुपये का चेक सौंपा।

मुख्यमंत्री ने इस सहयोग के लिए एचपीपीटीसीएल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस राशि से सुख आश्रय योजना के तहत आने वाले बच्चों और अन्य लाभार्थियों की देखभाल, शिक्षा और कल्याण से जुड़े कार्यों को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, सचिव (विद्युत) राकेश कंवर, एचपीपीटीसीएल के प्रबंध निदेशक आबिद हुसैन सादिक और उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) अनिल कुमार शर्मा भी मौजूद रहे।

जल शक्ति विभाग में 40 कनिष्ठ अभियंता बने सहायक अभियंता

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग ने 40 कनिष्ठ अभियंताओं (जेई) को सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया है। विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि यह फैसला 8 जुलाई 2026 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक की सिफारिशों के आधार पर लिया गया।

पदोन्नत अधिकारियों में 22 डिप्लोमा धारक और 18 स्नातक/एएमआईई श्रेणी के कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। श्रेणीवार देखें तो 21 सामान्य वर्ग, 6 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), 9 अनुसूचित जाति (एससी) और 4 अनुसूचित जनजाति (एसटी) के अधिकारियों को पदोन्नति मिली है।

इसके अलावा विभाग ने 12 कनिष्ठ अभियंताओं को एसडीओ (सब डिविजनल ऑफिसर) के पद पर भी पदोन्नत किया है। ये पदोन्नतियां निकट भविष्य में खाली होने वाले पदों के लिए की गई हैं।

डॉ. अभिषेक जैन ने कहा कि इन पदोन्नतियों से विभाग की तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता मजबूत होगी। इससे पेयजल, सिंचाई और जल संसाधन से जुड़ी परियोजनाओं का बेहतर और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि ये सभी पदोन्नतियां हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के अंतिम निर्णय के अधीन प्रभावी रहेंगी। विभाग का उद्देश्य लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है।

नाबार्ड ने मनाया 45वां स्थापना दिवस, ग्रामीण विकास पर जोर

शिमला/शैल। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय ने शिमला में अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास, कृषि, सहकारी संस्थाओं के आधुनिकीकरण और आपदा-रोधी आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई।

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. विवेक पठानियाँ ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में प्रदेश में 4,213 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त वितरित किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.3 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि इससे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश की 1,113 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) अब ई-पैक्स के रूप में कार्य कर रही हैं, जिससे किसानों को अधिक पारदर्शी और तेज सेवाएं मिलेंगी।

आरआईडीएफ के तहत वर्ष 2025-26 में 783 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें 50 पुल और पांच सड़कों का निर्माण शामिल है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सुविधाएं बेहतर होंगी।

डॉ. पठानियाँ ने बताया कि नाबार्ड अब जीआई टैग प्राप्त चंबा चप्पल की मूल्य श्रृंखला मजबूत करने और उसके बाजार का विस्तार करने पर विशेष ध्यान देगा। साथ ही ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और बिलासपुर में जिला विकास प्रबंधक का नया कार्यालय खोलने की जानकारी भी दी।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नाबार्ड ग्रामीण ऋण व्यवस्था, सहकारी संस्थाओं के आधुनिकीकरण, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु-अनुकूल आधारभूत ढांचे और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता रहेगा।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

स्वास्थ्य विभाग में 105 अतिरिक्त पदों पर भर्ती, 25 जुलाई तक करें आवेदन

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्वास्थ्य विभाग में 105 अतिरिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इन भर्तियों का उद्देश्य प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाना है।

इन पदों में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (ओटीए) के 60 पद, रेडियोग्राफर के 30 पद और वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन (एमएलटी ग्रेड-2) के 15 पद शामिल हैं। सभी नियुक्तियां जॉब ट्रेनी आधार पर की जाएंगी।

ये 105 पद पहले जारी भर्ती विज्ञापन संख्या 04/2026 के अतिरिक्त हैं। इससे पहले आयोग ने 196 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, जिनमें बाद में 18 और पद भी जोड़े गए थे।

अतिरिक्त पदों को शामिल करने के बाद आयोग ने तीनों पोस्ट कोड के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 11 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक दोबारा खोल दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 25 जुलाई 2026 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://hprca.hp.gov.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों ने पहले ही 28 फरवरी 2026 के मूल विज्ञापन या 30 मार्च 2026 के परिशिष्ट के तहत आवेदन किया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

चमियाना अस्पताल में 3 – टेस्ला एमआरआई मशीन शुरू

शिमला / शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अटल इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज (एआईएमएसएस), चमियाना में 3 – टेस्ला एमआरआई मशीन का शुभारंभ किया। करीब 23 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित यह मशीन प्रदेश की दूसरी सरकारी 3 – टेस्ला एमआरआई सुविधा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आधुनिक मशीन से मरीजों की तेज, सटीक और बेहतर गुणवत्ता वाली एमआरआई जांच हो सकेगी। अब मरीजों को जांच के लिए निजी अस्पतालों या अन्य स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नई तकनीक और आधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 125 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक ऑटोमेटेड लैब स्थापित की जाएंगी। साथ ही 800 नर्सों की भर्ती प्रक्रिया जारी है और दिसंबर तक 200 एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने एआईएमएसएस मोबाइल ऐप और अस्पताल की स्वच्छता निगरानी प्रणाली का भी शुभारंभ किया। उन्होंने अस्पताल तक बेहतर पहुंच के लिए ई – बस सेवा शुरू करने और संपर्क सड़क के निर्माण कार्य में तेजी लाने की भी बात कही।

नई औद्योगिक नीति जल्द होगी लागू, निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा: मुख्यमंत्री

शिमला / शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि नई नीति से राज्य में निवेश बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और मजबूती मिलेगी।

उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग – अनुकूल नीति तैयार करने के लिए सभी हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं। साथ ही उद्योगों को मंजूरी देने की एकल खिड़की प्रणाली को भी मजबूत किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने ऊना में बन रहे 2,071 करोड़ रुपये के बल्क ड्रग पार्क और धर्मशाला के यूनिटी मॉल की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को दोनों परियोजनाओं का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि बल्क ड्रग पार्क के लिए करीब 800 बीघा भूमि समतल की जा चुकी है। साथ ही अधिकारियों को 15 जुलाई तक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और स्टीम जनरेशन सुविधा का कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट, श्री प्रोडक्ट्स कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले के प्रमुख उत्पादों की पहचान करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोगों के लिए नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे।

आईटीआई के 30 प्रशिक्षु कजाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर दौरे पर जाएंगे

शिमला / शैल। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के 30 मेधावी प्रशिक्षुओं

का प्रतिनिधिमंडल कौशल विकास और आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण का अनुभव लेने के लिए कजाकिस्तान जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के नेतृत्व में यह दल 12 जुलाई को दिल्ली से रवाना होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू वर्चुअल माध्यम से प्रतिनिधिमंडल को रवाना करेंगे।

प्रतिनिधिमंडल में राज्य के 16 सरकारी आईटीआई के 30 प्रशिक्षु, तकनीकी शिक्षा निदेशक और तीन संकाय सदस्य शामिल हैं। इनमें 21 पुरुष और 9 महिला प्रशिक्षु हैं, जो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ड्राफ्ट्समैन (सिविल), इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, सूचना प्रौद्योगिकी, मशीनिस्ट, सर्वेयर, वायरमैन और टेक्नीशियन पावर इलेक्टॉनिक्स सिस्टम सहित 10 ट्रेडों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

राजेश धर्माणी ने कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट का उद्देश्य युवाओं को वैश्विक स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण से परिचित कराना है। कजाकिस्तान के अल्माटी में प्रशिक्षु हुंडई ट्रांसप्लांट और सामल वाटर बॉटलिंग प्लांट जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों का दौरा कर आधुनिक विनिर्माण प्रक्रियाओं और गुणवत्ता मानकों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा शिम्बुलक में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी गोंडोला आधारित केबल कार प्रणाली की इंजीनियरिंग और संचालन का भी अध्ययन करेंगे।

प्रतिनिधिमंडल अल्माटी मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, अल्माटी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और तूरान यूनिवर्सिटी का भी दौरा करेगा, जहां छात्र आदान – प्रदान, संयुक्त प्रमाणन पाठयक्रम और शैक्षणिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा होगी।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम से आईटीआई प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा और प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा। साथ ही, यह पहल भविष्य में अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक और औद्योगिक साझेदारियों को भी बढ़ावा देगी।

सुजानपुर में 7.54 करोड़ रुपये के विद्युत उप – केंद्र का शुभारंभ

शिमला / शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से हमीरपुर जिले के सुजानपुर विधानसभा

क्षेत्र में 7.54 करोड़ रुपये की लागत से बने 33/11 केवी विद्युत उप – केंद्र पटलांदर (अंसला) का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना के तहत चबुतरा से अंसला तक 7.2 किलोमीटर लंबी 33 केवी बिजली लाइन बिछाई गई है। इससे 16 ग्राम पंचायतों के करीब 14 हजार लोगों को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि नए उप – केंद्र से कोट चौरी, सुजानपुर, पटलांदर और पलाई फीडरों को बिजली आपूर्ति होगी। साथ ही इसे टौणी देवी और सुजानपुर उप – केंद्रों से भी जोड़ा गया है, ताकि आपात स्थिति में भी बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से कम वोल्टेज की समस्या दूर होगी, बिजली की हानि कम होगी और भविष्य की बढ़ती बिजली जरूरतों को भी पूरा किया जा सकेगा।

सुजानपुर के विधायक रणजीत सिंह राणा ने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र की 16 पंचायतों को सीधा लाभ मिलेगा।

हाई वैल्यू नट मिशन से बागवानों की आय बढ़ाने की तैयारी

शिमला / शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार बागवानों की आय बढ़ाने और बागवानी को आधुनिक बनाने के लिए 2026 से 2031 तक हाई वैल्यू नट मिशन शुरू करेगी। इस मिशन के तहत अखरोट, बादाम, खुमानी और चिलगोजा जैसी अधिक मूल्य वाली फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

सरकार का कहना है कि मिशन का उद्देश्य पुराने बागों का कायाकल्प, कम उत्पादन की समस्या का समाधान, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है।

योजना के तहत करीब 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। इनमें 900 हेक्टेयर पुराने और कम उत्पादन वाले बागों का वैज्ञानिक तरीके से पुनरुद्धार किया जाएगा। वहीं 100 हेक्टेयर में आधुनिक हाई – डेंसिटी मॉडल बाग विकसित किए जाएंगे, जहां बेहतर पौध, सूक्ष्म सिंचाई और जलवायु के अनुरूप खेती की तकनीक अपनाई जाएगी।

मिशन के तहत किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौधे उपलब्ध कराने के लिए चार हाई – टेक नर्सरी और दो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र प्रशिक्षण, अनुसंधान और आधुनिक बागवानी तकनीकों की जानकारी भी देंगे।

फसल की बेहतर कीमत दिलाने के लिए 10 आधुनिक संग्रह, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन केंद्र भी बनाए जाएंगे। इससे कटाई के बाद होने वाला नुकसान कम होगा और किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा।

सरकार किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को भी बढ़ावा देगी और निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही किसानों को विभिन्न वित्तीय योजनाओं का लाभ दिलाने के प्रयास किए जाएंगे।

जनजातीय क्षेत्रों में चिलगोजा के संरक्षण और पुनर्जीवन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए प्राकृतिक पुनर्जनन, सामुदायिक वन प्रबंधन और बीज तैयार करने की विशेष व्यवस्था की जाएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों की आय भी बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हाई वैल्यू नट मिशन से हिमाचल की बागवानी को नई दिशा मिलेगी। आधुनिक तकनीक, बेहतर पौध सामग्री, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देकर बागवानों की आय बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मिशन से ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और हजारों बागवान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

15 मई 2003 से पहले विज्ञापित पदों पर भर्ती कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ

शिमला / शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित पदों पर भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों को सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ दिया जाएगा।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे कर्मचारियों के एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान को उनके जीपीएफ खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही इस राशि पर जीपीएफ की निर्धारित ब्याज दर के अनुसार ब्याज भी मिलेगा।

उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी इस श्रेणी में आते हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें भी सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत सेवानिवृत्ति की तिथि से पेंशन का लाभ मिलेगा।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद 1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना लागू की थी और इसके लिए 4 मई 2023 को अधिसूचना जारी की गई थी।

सरकार के इस निर्णय से 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित पदों पर भर्ती हुए हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

आप कभी नहीं जान सकते कि आपके कार्यो का क्या परिणाम आएगा, लेकिन यदि आप कुछ नहीं करेंगे, तो कोई परिणाम नहीं आएगा।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

क्या सवाल पूछना भी अपराध हो गया है?

लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है। लोकतंत्र की असली पहचान यह है कि सरकार सवालों का जवाब दे, आलोचना को सुने और संस्थाओं पर जनता का भरोसा बनाए रखे। लेकिन पिछले कुछ वर्षो की घटनाओं ने यह चिंता गहरा दी है कि क्या देश में जवाबदेही की जगह प्रचार ने ले ली है? क्या युवाओं के भविष्य, जनता की आस्था और नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध जैसे गंभीर मुद्दे राजनीतिक शोर में दबते जा रहे हैं?

NEET पेपर लीक मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। करोड़ों छात्र वर्षो तक कठिन मेहनत करते हैं। परिवार अपनी जमा-पूंजी बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। लेकिन जब परीक्षा की गोपनीयता ही संदिग्ध हो जाए, तो सबसे बड़ा नुकसान किसी सरकार का नहीं, बल्कि उस छात्र का होता है जिसने अपनी पूरी युवा उम्र एक परीक्षा के भरोसे लगा दी। यदि एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं, तो यह केवल परीक्षा प्रणाली की विफलता नहीं, बल्कि शासन की जवाबदेही पर भी प्रश्नचिह्न है। इस समय सरकार द्वारा केवल कारवाई की घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं है भरोसा तभी लौटेगा जब ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति असंभव बना दी जाए।

इसी तरह, राम मंदिर करोड़ों भारतीयों की आस्था का केंद्र है। इस आस्था का सम्मान हर लोकतांत्रिक समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन आस्था जितनी पवित्र होती है, उससे जुड़े आर्थिक और प्रशासनिक प्रबंधन की जवाबदेही भी उतनी ही आवश्यक होती है। यदि किसी भूमि खरीद, दान राशि या वित्तीय लेन-देन को लेकर सवाल उठते हैं, तो उनका जवाब तथ्यों और पारदर्शिता से दिया जाना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक नारों से। यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि विभिन्न समय पर लगाए गए आरोपों में से कई न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाये निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता ही लोकतांत्रिक रास्ता है।

हाल ही में लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले NEET पेपर लीक में शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह पहला अवसर नहीं है जब विरोध प्रदर्शनों को लेकर सरकार पर सवाल उठे हों। किसान आंदोलन, पहलवानों का धरना, मणिपुर को लेकर प्रदर्शन और लद्दाख के मुद्दे हर बार यह बहस सामने आई कि क्या सरकार संवाद को प्राथमिकता देती है या विरोध को प्रशासनिक चुनौती मानकर देखती है।

आज की राजनीति में एक विचित्र प्रवृत्ति दिखाई देती है। जो सरकार में है, वह हर आलोचना को राष्ट्र-विरोध या राजनीतिक षडयंत्र बताने लगता है और जो विपक्ष में है, वह हर घटना को सरकार की पूर्ण विफलता घोषित कर देता है। इस टकराव में सबसे अधिक नुकसान जनता के भरोसे का होता है।

युवाओं का प्रश्न केवल रोजगार का नहीं, बल्कि अवसरों की समानता का भी है। यदि परीक्षा प्रणाली पर विश्वास नहीं रहेगा, तो प्रतिभा हतोत्साहित होगी। यदि शांतिपूर्ण विरोध पर संदेह की दृष्टि होगी, तो लोकतांत्रिक संवाद कमजोर होगा। यदि धार्मिक आस्था से जुड़े संस्थानों की पारदर्शिता पर सवालों का उत्तर तथ्यों से नहीं दिया जाएगा, तो संदेह और बढ़ेगा।

सरकार का दायित्व केवल योजनाएं घोषित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि संस्थाएं निष्पक्ष और विश्वसनीय रहें। विपक्ष की जिम्मेदारी केवल आरोप लगाने तक सीमित नहीं है उसे तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर सरकार से जवाब मांगना चाहिए।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति संसद नहीं, बल्कि जनता का विश्वास है। जब युवा परीक्षा पर भरोसा खोने लगें, नागरिक शांतिपूर्ण विरोध को लेकर आशंकित हों और आस्था भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाए, तब यह केवल किसी एक दल की समस्या नहीं रह जाती। यह पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए चेतावनी होती है।

सवाल यह नहीं है कि सत्ता में कौन है। सवाल यह है कि क्या देश की संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि किसी भी सरकार के रहते हुए जनता का विश्वास बना रहे? क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा केवल बहुमत से नहीं होती वह पारदर्शिता, जवाबदेही, संवैधानिक अधिकारों के सम्मान और असहमति के लिए खुले स्थान से होती है। यही वह कसौटी है जिस पर हर सरकार चाहे किसी भी दल की हो आंकी जाएगी।

पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन से ही वक्फ की गरिमा और मर्यादा वापस आ पाएगी

गौतम चौधरी

वक्फ़ इस्लाम की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं में से एक है। सदियों से मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, अनाथालय, दरगाहें और अनेक धर्मार्थ संस्थान उन संपत्तियों पर संचालित होते रहे हैं जिन्हें आम मुसलमानों ने अल्लाह के नाम पर समाज की भलाई के लिए समर्पित किया है। इन संपत्तियों का उद्देश्य किसी व्यक्ति, परिवार या संगठन का हित नहीं, बल्कि समुदाय और मानवता की सेवा है।

फिर भी एक गंभीर प्रश्न लगातार उठता है। यदि वक्फ़ के पास देशभर में विशाल संपत्ति है, तो उसका लाभ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक कल्याण के रूप में अपेक्षित स्तर पर क्यों दिखाई नहीं देता? यह प्रश्न किसी संस्था को कठघरे में खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य को पुन: स्थापित करने के लिए पूछा जाना चाहिए। यही प्रश्न जब मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर कासमी साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''नि:संदेह वक्फ की संपत्ति पर आज चंद परिवार और समुदायों का कब्जा है। यही कारण है कि उससे आम मुस्लिम समाज लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। यदि उस संपत्ति को आम के काम में लगाया जाए तो मुस्लिम-ए-हिंद का कायाकल्प हो सकता है।''

जब भी वक्फ़ प्रशासन में सुधार या पारदर्शिता की बात होती है, तो अक्सर इसे सरकारी हस्तक्षेप या धार्मिक स्वायत्तता पर हमले के रूप में देखा जाता है। वक्फ़ की स्वायत्तता निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है लेकिन स्वायत्तता का अर्थ जवाबदेही से मुक्त होना नहीं हो सकता। किसी भी सार्वजनिक या धर्मार्थ संस्था की विश्वसनीयता उसके पारदर्शी संचालन से ही बनती है। इस मामले में भी कासमी साहब का अपना रुख है, वे कहते हैं, ''हम हिंदुस्तान के मुसलमान सरकार के साथ हैं लेकिन वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को सदस्य बनाना हमारे साथ अन्याय है।'' मुफ्ती साहब आगे कहते हैं, ''मैं मानता हूं कि इसमें सरकार की मंशा ठीक ही होगी लेकिन क्या किसी हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड में मुसलमान सदस्य हो सकता है? हम वक्फ के ऑडिट आदि नियमों के लिए सरकार का समर्थन करते हैं लेकिन गैर मुस्लिम का हस्तक्षेप हम बरदास्त नहीं कर सकते।''

इधर वक्फ को लेकर और कई चौकाने वाले मामले सामने आए हैं। हाल में जयपुर के जामियातुल हिदाया ट्रस्ट से जुड़े भूमि लेनदेन को लेकर विवाद सामने आया है। इस मामले में कुछ प्रमुख व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें और एफआईआर दर्ज हुई हैं। संबंधित पक्षों ने सभी आरोपों से इन्कार किया है और अपने लेनदेन को वैध बताया है। ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पर ही छोड़ना चाहिए। किसी पर आरोप लगना और दोष सिद्ध होना अलग-अलग बातें हैं लेकिन मामला तो है। यह मामला गंभीर भी है। इसको लेकर विवाद पैदा हो रहा है। ऐसे विवाद एक व्यापक प्रश्न खड़ा करता है। यदि वक्फ़ जैसी सामुदायिक संस्था से जुड़े मामलों पर प्रश्न उठते हैं, तो क्या समुदाय को पारदर्शिता की मांग नहीं करनी चाहिए? क्या जवाबदेही को धर्म या समुदाय पर हमला मान लेना उचित है? प्रश्न बेहद गंभीर है।

इस गंभीर प्रश्न पर मुफ्ती साहब का कहाना है, ''इस्लामी परंपरा स्वयं अमानत, ईमानदारी और न्याय पर आधारित है। कुरान और पैग़म्बर मुहम्मद सल्लाहो वसल्लम की शिक्षाएं सार्वजनिक संपत्ति और विश्वास की रक्षा पर विशेष बल देती हैं। इसलिए वक्फ़ संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन की मांग इस्लाम-विरोधी नहीं, बल्कि इस्लामी मूल्यों के अनुरूप है।''

वास्तविक चिंता यह है कि यदि वक्फ़ संपत्तियों का प्रभावी प्रबंधन नहीं होता, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान आम मुसलमानों को उठाना पड़ता है। जिन संसाधनों से विद्यालय, छात्रवृत्तियां, अस्पताल, कौशल विकास केंद्र और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालित हो सकते थे, वे अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। यदि वक्फ़ संपत्तियों का वैज्ञानिक, पारदर्शी और पेशेवर ढंग से प्रबंधन किया जाए, तो वे मुस्लिम समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

समय आ गया है कि वक्फ़ प्रशासन में कुछ बुनियादी सुधारों पर गंभीरता से विचार किया जाए। सभी वक्फ़ संपत्तियों का डिजिटल अभिलेखीकरण और मानचित्रण हो, नियमित ऑडिट सार्वजनिक किए जाएं, आय-व्यय का विवरण उपलब्ध कराया जाए, पट्टा और विकास संबंधी समझौतों में पारदर्शिता लाई जाए तथा स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाए। धार्मिक प्रतिष्ठा या सामाजिक प्रभाव किसी भी संस्था या व्यक्ति को सार्वजनिक जवाबदेही से ऊपर नहीं रख सकता।

वक्फ़ की प्रतिष्ठा केवल बाहरी आलोचनाओं का विरोध करने से नहीं बचेगी, बल्कि अपने भीतर सर्वोच्च स्तर की ईमानदारी और पारदर्शिता स्थापित करने से मजबूत होगी। जयपुर विवाद का अंतिम कानूनी परिणाम चाहे जो हो, उसने एक महत्वपूर्ण संदेश अवश्य दिया है-''पारदर्शिता वक्फ़ के लिए खतरा नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।'' मुफ्ती साहब कहते हैं, ''वक्फ़ समुदाय की धरोहर है। उसकी रक्षा का सर्वोत्तम मार्ग यह सुनिश्चित करना है कि उसका प्रत्येक संसाधन उसी उद्देश्य की पूर्ति करे, जिसके लिए उसे समर्पित किया गया है-समाज की सेवा, न्याय और जनकल्याण।''

राजीव गांधी वन संवर्धन योजना से महिला व युवक मंडलों को मिला हरित भविष्य संवारने का दायित्व

पर्यावरण संरक्षण के साथ ही आजीविका के भी खुल रहे नए द्वार

बदलते जलवायु परिदृश्य और पर्यावरण संरक्षण की बढ़ती आवश्यकता के बीच प्रदेश सरकार की राजीव गांधी वन संवर्धन योजना जनभागीदारी आधारित हरित विकास का सशक्त मॉडल बनकर उभर रही है। योजना के माध्यम से महिला मंडलों और युवक मंडलों को पौधरोपण तथा पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपकर पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। इससे जहां एक ओर ग्रामीण महिलाओं और युवाओं की

आजीविका को नई मजबूती मिल रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के वन क्षेत्र के संरक्षण एवं संवर्धन को भी बल मिल रहा है।

'मंडी वन मंडल में 20 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए गए 16 हजार पौधे'

वन मंडल मंडी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 8 महिला मंडलों और दो युवक मंडलों के माध्यम से 20 हेक्टेयर क्षेत्र में 16,000 पौधों का रोपण कराया गया। वन विभाग द्वारा पौधरोपण एवं संरक्षण कार्य के लिए महिला और युवक मंडलों को एक हैक्टेयर के लिए एक लाख 20 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

पौधरोपण में बान, देवदार, दाडू, कचनार, शीशम, आंवला, बेहड़ा, रीठा, जामुन और पाजा जैसी स्थानीय एवं बहुपयोगी प्रजातियों को प्राथमिकता दी गई। इन पौधों का वितरण कोटली, कटौला, मंडी, द्रंग और पनारसा रेंज की रानी बाई, त्वांबड़ा, कमांद, कटौला, मेहसरा, कुन्नू, सरौन तथा शाला नाल नर्सरियों से किया गया।

'वैज्ञानिक पद्धति से हुआ पौधरोपण'

योजना के अंतर्गत मंडी वन मंडल में माइक्रो प्लान के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से पौधरोपण किया गया, जिससे पौधों के बेहतर विकास और दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके।

'महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बनी योजना की सबसे बड़ी ताकत'

योजना की सबसे बड़ी विशेषता स्थानीय महिला मंडलों और युवक मंडलों की सक्रिय सहभागिता है। वन विभाग का मानना है कि स्थानीय समुदाय पौधरोपण के साथ-साथ उनकी नियमित देखभाल एवं संरक्षण भी प्रभावी ढंग से करेगा, जिससे पौधों के जीवित रहने की दर में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता और रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रही है।

'युवाओं ने जताया मुख्यमंत्री का आभार'

मंडी के शांडला स्थित एकता युवक मंडल के अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ युवाओं और महिला मंडलों को प्रकृति से जोड़ने की दिशा में एक सराहनीय एवं दूरदर्शी पहल है। पौधरोपण अभियान में सिद्धि विनायक महिला मंडल की अध्यक्ष गरिमा, महिला मंडल सलेतर की अध्यक्ष नंदा कुमारी, महिला मंडल लक्ष्मी, सिऊण की अध्यक्ष शकुंतला देवी, पार्वती स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष वंदना देवी, नवज्योति महिला मंडल, सिराम की अध्यक्ष लज्जा देवी, नेहरू युवक मंडल, रियूर के अध्यक्ष दुष्यंत ठाकुर, नाग नाला महिला मंडल की अध्यक्ष प्रेमलता शर्मा तथा दारुणाल युवक मंडल के अध्यक्ष राम प्रकाश ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

सभी महिला मंडलों एवं युवक मंडलों के प्रतिनिधियों ने पौधरोपण के उपरांत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हुए कहा कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना पर्यावरण संरक्षण, जनसहभागिता और हरित हिमाचल के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक पहल है।

'वन वृत्त मंडी में 121.5 हेक्टेयर क्षेत्र के कार्य स्वीकृत'

वन वृत्त मंडी में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत वन विकास एवं आजीविका संवर्धन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य हरित आवरण बढ़ाना, वन आधारित आजीविका को सुदृढ़ करना तथा स्थानीय लोगों में वनों के प्रति स्वामित्व एवं संरक्षण की भावना विकसित करना है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 121.5 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कार्य स्वीकृत किए गए, जिनके लिए लगभग 1 करोड़ 24 लाख 20 हजार रुपये की राशि आवंटित की गई। इस अवधि में 102.5 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया तथा लगभग 1 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय उपलब्धि अर्जित की गई। योजना के तहत 74 महिला एवं युवक मंडलों को लाभान्वित करते हुए 1,22,857 पौधे/पॉलियों का वितरण किया गया।

'हरित हिमाचल की मजबूत नींव बन रही योजना'

राजीव गांधी वन संवर्धन योजना केवल पौधरोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी, सहभागिता और स्वामित्व की भावना विकसित करने का व्यापक अभियान है। महिला मंडलों, युवक मंडलों, वन विभाग और स्थानीय समुदाय की साझेदारी इस योजना को हरित हिमाचल के निर्माण की मजबूत आधारशिला बना रही है।

पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संतुलन और ग्रामीण विकास को समान प्राथमिकता देने वाली यह योजना आने वाले वर्षों में प्रदेश के लिए एक प्रेरणादायक म डल बनने की क्षमता रखती है। वन संरक्षण, पारिस्थितिक संतुलन एवं समावेशी विकास की दिशा में राज्य सरकार के सतत प्रयास पर्यावरणीय स्थिरता और सामुदायिक कल्याण को नई मजबूती प्रदान कर रहे हैं।

तमरोह क्लस्टर में जापानी फल की दस्तक: एचपी शिवा परियोजना बनी सहारा

25 हेक्टेयर भूमि में जापानी फल की लोकप्रिय 'फ्यू' किस्म के लगाए जा रहे 15 हजार पौधे

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्यवर्धन (एचपी शिवा) परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य पारंपरिक खेती को आधुनिक एवं लाभकारी बागवानी से जोड़ते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। इसी सोच का परिणाम है मंडी जिले के उपमंडल बल्ह का तमरोह क्लस्टर आज जापानी फल उत्पादन के एक उभरते केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, जिससे क्षेत्र के किसानों के लिए समृद्धि और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

'सुक्खू सरकार' की महत्वाकांक्षी एचपी शिवा परियोजना प्रदेश के किसानों को पारंपरिक खेती से उच्च मूल्य वाली बागवानी की ओर अग्रसर कर रही है। जापानी फल (पर्सिमन) की व्यावसायिक खेती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी में है।

हाल ही में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने निर्माणाधीन तमरोह क्लस्टर का दौरा कर परियोजना की प्रगति का जायजा लिया था। यह क्लस्टर न केवल आधुनिक बागवानी का मॉडल बन रहा है, बल्कि सामाजिक समावेश और किसान सशक्तिकरण का उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है।

तमरोह क्लस्टर से अब तक कुल 76 बागवान जुड़ चुके हैं। इनमें 35 अनुसूचित जाति वर्ग, 36 सामान्य वर्ग तथा पांच महिला किसान-बागवान शामिल हैं। परियोजना के अंतर्गत लगभग 25 हेक्टेयर भूमि में जापानी फल की लोकप्रिय 'फ्यू' किस्म के करीब 15 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 12.500 हेक्टेयर भूमि पर 7,485 पौधे सफलतापूर्वक रोपित किए जा चुके हैं, जबकि शेष भूमि पर पौधारोपण कार्य शीतकालीन मौसम में किया जाएगा। पौधों के फल देना शुरू होने के बाद क्षेत्र के किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

परियोजना के तहत सिंचाई व्यवस्था को सु ढ़ बनाने के लिए दो लाख लीटर तथा तीन लाख लीटर की क्षमता के (दो) फेब्रिकेटेड स्टोरेज टैंक स्थापित किए गए हैं। इससे पौधों को वर्षभर आवश्यक सिंचाई उपलब्ध करवाई जा सकेगी और जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इस पूरे क्लस्टर में सोलर फेंसिंग भी की जा चुकी है।

तमरोह क्लस्टर की सफलता में तकनीकी मार्गदर्शन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। गत मई, 2026 में एशियन विकास बैंक (एडीबी) की टीम के माध्यम से फिलीपींस और उत्तराखण्ड से डॉ. डेनिस लोपेज, डॉ. दिनेश गोडे, डॉ. प्राची शर्मा, डॉ. ब्रांडो विशेषज्ञों की टीम ने क्लस्टर का दौरा किया। विशेषज्ञों ने किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों, पौधों के वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रूनिंग, सिंचाई और उत्पादन बढ़ाने के उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान किसानों को सफल बागवानी मॉडलों से भी अवगत करवाया गया।

परियोजना के अंतर्गत किसानों को पौधे, ड्रिप सिंचाई, फेंसिंग, तकनीकी प्रशिक्षण तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। विभागीय टीम नियमित रूप से क्लस्टर का दौरा कर पौधारोपण, सिंचाई प्रबंधन, पौधों की देखभाल, प्रूनिंग, पोषण प्रबंधन तथा रोग एवं कीट नियंत्रण संबंधी तकनीकी जानकारी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, किसान गोष्ठियां और विशेषज्ञों के भ्रमण भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि बागवान आधुनिक तकनीकों को अपनाकर बेहतर उत्पादन और अधिक आय अर्जित कर सकें।

उपनिदेशक बागवानी मंडी डॉ. संजय गुप्ता ने कहा कि एचपी शिवा परियोजना प्रदेश में बागवानी क्षेत्र के विस्तार और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों से जोड़ते हुए वैज्ञानिक ढंग से फल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

तमरोह क्लस्टर आने वाले वर्षों में केवल जापानी फल उत्पादन का केंद्र ही नहीं बनेगा, बल्कि यह प्रदेश में आधुनिक बागवानी आधारित ग्रामीण विकास का एक सफल मॉडल भी साबित हो सकता है। यदि यह प्रयास अपेक्षित परिणाम देता है तो बल्ह क्षेत्र तथा साथ लगते क्षेत्र की पहचान पारंपरिक खेती के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता वाले जापानी फल उत्पादन के लिए भी होगी।

प्राकृतिक खेती से सुदृढ़ हो रही प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था

राज्य अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला में प्राकृतिक उत्पादों की होगी गुणवत्ता जांच

हिमाचल की माटी पर किसानों की समृद्धि की नई ईबारत लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने समृद्धि की इस कहानी की रूप रेखा तैयार की है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से किसानों के जीवन में खुशहाली आ रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा प्रदान कर रही है।

हिमाचल प्रदेश, देश का पहला राज्य है, जिसने प्राकृतिक खेती से तैयार की गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। वर्ष-दर-वर्ष इसमें उल्लेखनीय वृद्धि भी की जा रही है। अब प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए गेहूं की खरीद 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्की 50 रुपये प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी 150 रुपये प्रति किलोग्राम, पांगी घाटी की जौ 80 रुपये प्रति किलोग्राम तथा अदरक की 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद की जा रही है।

सरकार के सतत प्रयासों से किसानों का प्राकृतिक खेती के प्रति रुझान बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 में 838 किसानों से 2123.58 क्विंटल गेहूं की खरीद की तुलना में इस रबी के सीजन में प्रदेश सरकार ने 1,891 किसानों से प्राकृतिक पद्धति से उत्पादित 2,679.89 क्विंटल गेहूं की खरीद सुनिश्चित की है।

मुख्यमंत्री प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के गुणवत्तायुक्त एवं पोषण युक्त प्राकृतिक खाद्यान्नों को विशेष पहचान और बाजार दिलवाने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं। जिला चंबा के पांगी उप-मंडल को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उप-मंडल घोषित किया गया है। इससे क्षेत्र के लोग अपनी पारंपरिक कृषि पद्धतियों का संरक्षण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। विगत खरीफ सीजन में पांगी उप-मंडल की हुडान, सुराल, किलाड़, सांच और सेचु पंचायत के किसानों ने अच्छे दाम में जौ की बिक्री सुनिश्चित की।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में बड़ा भंगाल के प्रवास के दौरान अधिकारियों को किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, बड़ा भंगाल क्षेत्र को प्राकृतिक खेती पंचायत और क्षेत्र में उत्पादित राजमाह के लिए जीआई टैग प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

वर्तमान में प्रदेश के 2,56,870 किसान 44,784.73 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की नई पहलों के बाद प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए कृषि विभाग में अलग मार्केटिंग विंग स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। समृद्ध किसान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वैज्ञानिक, अनुसंधान और व्यवहारिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। इस दिशा में किसानों के प्राकृतिक उत्पादों और बीज की जांच की सुविधा के लिए जिला हमीरपुर में 8.64 करोड़ रुपये की लागत से राज्य अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इस प्रयोगशाला के स्थापित होने से कृषि उत्पादों विशेषकर प्राकृतिक उत्पादों की वैज्ञानिक जांच सुनिश्चित होगी। यह प्रयोगशाला अत्याधुनिक विश्लेषणात्मक उपकरणों से लैस है जो कृषि उत्पादों में मौजूद सूक्ष्म तत्वों का भी सटीकता से पता लगाने में सक्षम है। प्रयोगशाला में प्राकृतिक उत्पादों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता की जांच की जाएगी।

प्रदेश में शून्य बजट प्राकृतिक खेती पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे लोगों की सेहत के साथ मिट्टी की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हिमाचल का प्राकृतिक खेती मॉडल देश के प्राकृतिक खेती मिशन में नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है।

मार्च – अप्रैल 2027 तक शुरू होगी 450 मेगावाट शोंगटोंग – कड़छम जलविद्युत परियोजना: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने किन्नौर जिले में निर्माणाधीन 450 मेगावाट शोंगटोंग – कड़छम जलविद्युत परियोजना

को मार्च – अप्रैल 2027 तक शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजना के पावर हाउस का करीब 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मानसून के दौरान भी बांध का निर्माण जारी रहेगा। इसके लिए सतलुज नदी के पानी को कुछ गेटों के जरिए मोड़ा जाएगा, जबकि अन्य गेटों पर समानांतर रूप से काम चलता रहेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और हिमाचल की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। यह परियोजना प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत बनाने के साथ – साथ पर्यावरण – अनुकूल विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और तकनीकी चुनौतियों के बावजूद सरकार लगातार निगरानी कर रही है और आधुनिक तकनीकी उपायों के जरिए परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

परियोजना पूरी होने के बाद हर साल करीब 1,579 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इससे प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और बिजली ग्रिड भी अधिक मजबूत होगा। सरकार का अनुमान है कि इस परियोजना से हर वर्ष लगभग 900 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ राज्य को मिलेगा।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आबिद हुसैन सादिक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने 'वॉटर लॉज ऑफ हिमाचल' पुस्तक का विमोचन किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 'वॉटर लॉज ऑफ हिमाचल' संकलन का

विमोचन किया। जल शक्ति विभाग द्वारा तैयार की गई यह राज्य की पहली ऐसी संदर्भ पुस्तक है, जिसमें विभाग से जुड़े प्रमुख कानून, नियम, नीतियां, तकनीकी दिशा – निर्देश और प्रशासनिक आदेश एक ही स्थान पर संकलित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक अधिकारियों, अभियंताओं, ठेकेदारों और आम लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। इससे जलापूर्ति, सीवरेज और सिंचाई से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत 99.9 प्रतिशत घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया है। साथ ही राज्य को 2026 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी मिला है।

इस संकलन में जल शुल्क, निविदा प्रक्रिया, वित्तीय नियम, जल गुणवत्ता परीक्षण, कानूनी प्रावधान और लोक सेवा गारंटी अधिनियम से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में दी गई है। इससे अधिकारियों को निर्णय लेने में और आम लोगों को विभागीय सेवाओं की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मुख्यमंत्री के सचिव आशीष सिंहमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

साल के अंत तक सभी मेडिकल कॉलेजों में होंगे आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक प्रदेश के सभी सरकारी

चिकित्सा महाविद्यालयों को अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस किया जाएगा, ताकि लोगों को बेहतर इलाज के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी दूर करने के लिए हजारों पदों पर भर्ती की है और मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि टांडा, हमीरपुर और एआईएमएसएस चमियाना में आधुनिक जांच प्रयोगशालाओं के लिए 75 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वहीं, आईजीएमसी शिमला में पीईटी स्कैन मशीन शुरू हो चुकी है, जबकि टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए भी पीईटी स्कैन मशीनें खरीदी जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 71 पैरामेडिकल और 50 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा 162 नए पैरामेडिकल पद भी स्वीकृत किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि आईजीएमसी शिमला में नए लेक्चर थिएटर और परीक्षा भवन के निर्माण के लिए 5.76 करोड़ रुपये, जबकि टांडा मेडिकल कॉलेज में लेक्चर थिएटर के लिए 14.13 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एआईएमएसएस चमियाना में निर्माणाधीन क्रिटिकल ब्लॉक और अतिरिक्त ब्लॉक के कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश के लोगों को अपने घर के पास ही आधुनिक और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

एचपीएमसी ने शुरू की कांच की बोतलों की बायबैक योजना

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) ने पर्यावरण संरक्षण और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए खाली कांच की बोतलों की बायबैक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उपभोक्ता, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर इस्तेमाल की गई एचपीएमसी की कांच की बोतलें वापस कर आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त कर सकेंगे।

योजना के अनुसार, उपभोक्ताओं को 200 मिलीलीटर की प्रत्येक खाली बोतल लौटाने पर 1 रुपये और 600 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतल पर 2 रुपये दिए जाएंगे। वहीं, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को संग्रहण और आपूर्ति के विभिन्न चरणों में प्रति बोतल 4 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा।

एचपीएमसी की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, खाली बोतलों का संग्रह अधिकृत रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और एचपीएमसी कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद इन्हें छंटाई और रीसाइक्लिंग के लिए जरोल स्थित एचपीएमसी के फल प्रसंस्करण संयंत्र भेजा जाएगा। बोतलों के संग्रह और परिवहन के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है।

निगम ने उपभोक्ताओं, रिटेलरों और डिस्ट्रीब्यूटर्स से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए कहा है कि यह पहल कांच के कचरे को कम करने, रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने और हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ एवं हरित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए हिमाचल में 3,500 करोड़ की आपदा – रोधी आधारभूत संरचना बनेगी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए करीब 3,500

करोड़ रुपये की लागत से आपदा – रोधी आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी। उन्होंने यह बात शिमला में आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यशाला के समापन समारोह में कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 की आपदा से सरकार ने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे। उस दौरान करीब 75 हजार पर्यटक विभिन्न क्षेत्रों में फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया। उन्होंने बताया कि आपदा में 23 हजार मकान क्षतिग्रस्त हुए और 51 लोगों की जान गई। इसके बाद सरकार ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया।

उन्होंने कहा कि 2023 के अनुभवों के कारण सरकार वर्ष 2025 की आपदा से बेहतर तरीके से निपट सकी। मुख्यमंत्री ने बढ़ती बादल फटने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए इसे जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय कारणों से जुड़ी चुनौती बताया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने टुवर्ड्स रेजिलिएंट हिमाचल प्रदेश रिपोर्ट का विमोचन किया और हिमाचल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (एसआईएयू) पोर्टल भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल बेहतर योजना निर्माण और विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने में मदद करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल क्षतिग्रस्त ढांचे का पुनर्निर्माण करना नहीं, बल्कि भविष्य की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में सक्षम मजबूत और सुरक्षित आधारभूत संरचना तैयार करना है।

नौणी विश्वविद्यालय में वाइन मेकिंग का 3 माह का व्यावसायिक कोर्स, आवेदन शुरू

शिमला/शैल। डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (नौणी) ने कृषि उद्यमिता और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए तीन माह का वाइन मेकिंग व्यावसायिक पाठयक्रम शुरू किया है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

इस कोर्स में प्रतिभागियों को फलों के चयन, जूस निकालने, फर्मेंटेशन, वाइन तैयार करने, बॉटलिंग, गुणवत्ता जांच, पैकेजिंग और वाइनरी प्रबंधन का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही लघु वाइन उद्योग स्थापित करने की जानकारी भी दी जाएगी।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एच.एस. बवेजा ने कहा कि फलों का मूल्य संवर्धन किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने का प्रभावी माध्यम है।

कोर्स में 10 सीटें हैं। आवेदन के लिए 10 + 2 या समकक्ष परीक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोर्स की फीस 18,000 रुपये है।

आवेदन की अंतिम तिथि 8 अगस्त 2026, काउंसलिंग 14 अगस्त और कोर्स 20 अगस्त 2026 से शुरू होगा। इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर निर्धारित दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय के खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

वीबी – जी – राम – जी योजना हिमाचल के हित में नहीं, केंद्र से उठाएंगे मामला: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रस्तावित वीबी – जी – राम – जी

योजना हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को राज्य सरकार केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत पहले केंद्र सरकार 100 प्रतिशत धनराशि देती थी, जबकि नई योजना में 10 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा। इससे हिमाचल पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निर्माणाधीन पंचायत घरों को पूरा करने के लिए 30 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। वहीं ऊना में बन रहे जिला पंचायत संसाधन केंद्र के लिए भी अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अब तक 310 स्वयं सहायता समूहों को 65.56 लाख रुपये की ऋण सहायता दी गई है। इनके उत्पादों की बिक्री के लिए शिमला में हिमाचल हाट बनाया जा रहा है। इसके अलावा पंडोह और कुल्लू में भी नए शोरूम खोले जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभाग की सभी योजनाओं को मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से जोड़ने के निर्देश दिए, ताकि उनकी ऑनलाइन निगरानी और प्रभावी ढंग से की जा सके।

धर्मशाला में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का नया कार्यालय शुरू, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से धर्मशाला में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नए कार्यालय का शुभारंभ किया। यह कार्यालय हाल ही में शिमला से

धर्मशाला स्थानांतरित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा और आसपास के जिलों में बड़ी संख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोग रहते हैं। अब उन्हें आयोग से जुड़े कार्यों के लिए शिमला नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी।

उन्होंने कांगड़ा के उपायुक्त को धर्मशाला में रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) का कार्यालय भी जल्द शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी घोषित किया है और इसी के तहत विभिन्न सरकारी कार्यालय वहां स्थानांतरित किए जा रहे हैं। भविष्य में भी अन्य कार्यालय कांगड़ा लाने की योजना है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार डोडरा – क्वार क्षेत्र को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और बड़ा भंगाल क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास कर रही है।

शिमला के बैंटनी में डिजिटल संग्रहालय का शुभारंभ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला के बैंटनी में अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह

संग्रहालय हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, इतिहास और विरासत को आधुनिक तकनीक के माध्यम से संरक्षित करने और दुनिया तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल संग्रहालय अतीत और भविष्य के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करेगा। इसमें हाई-रेजोल्यूशन 3डी स्कैनिंग, वर्चुअल रियलिटी (वीआर), ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर), इंटरैक्टिव टाइमलाइन और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है।

संग्रहालय में शिमला के विकास का इतिहास, हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत, कालका – शिमला रेलवे, राज्य गठन के बाद की विकास यात्रा, लोक परंपराएं, हस्तशिल्प, स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान और पारंपरिक खान – पान को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों के लिए राज्य की धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ – साथ हिमाचल की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधायक हरीश जनारथा, शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

किशाऊ के बाद अब बीबीएमबी के 4200 करोड़ रुपये के एरियर पर सुक्खू सरकार का फोकस

शिमला/शैल। किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल के हित सुरक्षित होने के बाद अब राज्य सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से अपने बकाया अधिकार और एरियर की राशि हासिल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस मुद्दे पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से फोन पर बातचीत की। उन्होंने केंद्र सरकार से सहयोग मांगते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश लंबे समय से अपने वैधानिक अधिकारों का इंतजार कर रहा है और अब राज्य सरकार इन्हें हर हाल में हासिल करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश किशाऊ बांध परियोजना में तभी आगे बढ़ेगा, जब हरियाणा सरकार बीबीएमबी से जुड़े बकाया भुगतान पर अपनी सहमति देगी और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में शपथ – पत्र दाखिल करेगी। उनका कहना है कि जब तक हिमाचल को उसके पुराने अधिकार नहीं मिलते, तब तक नई परियोजनाओं में सहयोग की उम्मीद उचित नहीं है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि सुप्रीम कोर्ट करीब 15 वर्ष पहले ही बीबीएमबी की परियोजनाओं और उनसे मिलने वाले लाभ में हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी को मान्यता दे चुका है। इसके बावजूद राज्य को पिछले कई वर्षों से अपने हिस्से की 13,066 मिलियन यूनिट बिजली और उससे जुड़े आर्थिक लाभ नहीं मिले हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अब बीबीएमबी से अपने हिस्से के करीब 4,200 करोड़ रुपये के बकाया की वसूली के लिए कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर कारवाई कर रही है। यह पैसा हिमाचल प्रदेश का अधिकार है और सरकार इसे प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करेगी।

मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आश्वासन दिया कि वह इस मामले पर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। सरकार ने यह भी कहा कि किशाऊ बांध परियोजना में पुराने समझौते को बदलने के बाद अब हिमाचल प्रदेश को बिना कोई निवेश किए हर साल करीब 600 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा, जिसे राज्य के हित में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

सीबीएसई सरकारी स्कूलों के लिए 3,468 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी: शिक्षा मंत्री

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों के लिए 3,468 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। इनमें

2,668 नियमित पदों का मामला हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को भेजा जा चुका है, जबकि 800 अस्थायी अंग्रेजी और गणित शिक्षकों की नियुक्ति भी की जा रही है।

शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 158 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम की मंजूरी मिली है, जिनमें से 146 स्कूलों को सीबीएसई संबद्धता प्राप्त हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि डॉ. वाई.एस. परमार डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत अब तक 9,359 विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जा चुके हैं। शेष पात्र विद्यार्थियों को भी जल्द डीबीटी के माध्यम से लाभ दिया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल आईसीटी से जुड़ चुके हैं। 524 स्कूलों में पुराने कंप्यूटर बदले जाएंगे, जबकि 777 स्कूलों में बेहतर इंटरनेट सुविधा के लिए बीएसएनएल के साथ प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

उन्होंने कहा कि 870 शारीरिक शिक्षा अध्यापक (पीईटी) पदों की भर्ती शुरू हो चुकी है और 6,703 मल्टी टास्क वर्कर नियुक्त किए जा चुके हैं। शेष पदों को भी जल्द भरा जाएगा।

बैठक में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को भर्ती, डिजिटल शिक्षा, आपदा प्रभावित स्कूलों के पुनर्निर्माण और अन्य योजनाओं का कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए।

हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के दौरान किसी भी नेटवर्क से कर सकेंगे कॉल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के दौरान मोबाइल नेटवर्क बाधित होने पर लोगों को अब संचार में परेशानी नहीं होगी। दूरसंचार विभाग (हिमाचल प्रदेश एलएसए) जरूरत पड़ने पर इंट्रा सर्किल रोमिंग (आईसीआर) सुविधा सक्रिय करेगा, जिससे उपभोक्ता किसी भी उपलब्ध मोबाइल नेटवर्क का उपयोग कर कॉल कर सकेंगे।

विभाग के अनुसार, आपदा की स्थिति में यदि किसी मोबाइल कंपनी का नेटवर्क बंद हो जाता है, तो उपभोक्ता अपने फोन की सेटिंग में जाकर मैन्युअल रूप से उपलब्ध दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर का नेटवर्क चुन सकते हैं। इससे वे अपने परिजनों से संपर्क करने और राहत एवं बचाव कार्यों के दौरान जरूरी संचार बनाए रखने में सक्षम होंगे।

दूरसंचार विभाग ने बताया कि वर्ष 2025 में हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान चंबा, कुल्लू, लाहौल – स्पीति और मंडी के थुनाग क्षेत्र में यह सुविधा सफलतापूर्वक लागू की गई थी।

विभाग ने कहा कि जब भी इंट्रा सर्किल रोमिंग सुविधा लागू की जाएगी, तब प्रभावित क्षेत्रों और इसकी अवधि की जानकारी आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी, ताकि लोग आवश्यकता पड़ने पर इसका लाभ उठा सकें।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

गारंटीयों से 'सुखी परिवार' तक सवालों के घेरे में सुक्खू सरकार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश की राजनीति अब नए दौर में पहुंच चुकी है। विपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को एक साथ जोड़कर बड़ा राजनीतिक अभियान शुरू कर दिया है। चुनावी गारंटियां, घटता बजट, बढ़ता कर्ज, सरकारी योजनाओं की रफ्तार, एचआरटीसी की बदहाल स्थिति और प्रशासनिक फैसले अब भाजपा के प्रमुख हमले का आधार बन गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार इन मुद्दों को उठाकर सरकार को घेर रहे हैं। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव को 'गारंटी बनाम हकीकत' के मुद्दे पर लड़ने की तैयारी कर रही है।

सबसे ज्यादा विवाद मुख्यमंत्री की प्रस्तावित 'सुखी परिवार योजना' को लेकर है। भाजपा का आरोप है कि सरकार नई योजनाओं की घोषणा तो कर रही है, लेकिन उनके लिए बजट की व्यवस्था नहीं है। विपक्ष का कहना है कि समाज कल्याण विभाग का बजट पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 63 प्रतिशत घटकर 1618 करोड़ रुपये से 604 करोड़ रुपये रह गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नई योजना का खर्च सरकार कैसे उठाएगी। भाजपा का दावा है कि जब पुरानी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा, तब नई योजनाएं केवल घोषणा बनकर रह सकती हैं।

विपक्ष का हमला केवल बजट तक सीमित नहीं है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री की कई योजनाओं को 'चाइनीज खिलौना' बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार पहले बड़ी घोषणा करती है, लेकिन बाद में योजनाएं ठंडी पड़ जाती हैं। भाजपा का कहना है कि सरकार जमीन पर काम करने की बजाय प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रही है। विपक्ष दावा कर रहा है कि विधानसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार फ्लैगशिप योजनाओं पर खर्च कम हुआ, जबकि प्रचार-प्रसार पर ज्यादा पैसा खर्च किया गया।

भाजपा अब कांग्रेस की चुनावी गारंटियों को सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रही है। विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि पांच लाख रोजगार, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, दूध के बढ़े हुए समर्थन मूल्य और अन्य चुनावी वादों की स्थिति क्या है। भाजपा का कहना है कि जनता अब घोषणाएं नहीं, बल्कि उनका परिणाम देखना चाहती है।

सरकार की कार्यशैली भी विपक्ष के निशाने पर है। जयराम ठाकुर का आरोप है कि फैसले संस्थागत व्यवस्था के बजाय कुछ चुनिंदा लोगों के प्रभाव में लिए जा रहे हैं। भाजपा का दावा है कि सरकार के भीतर भी असंतोष बढ़ रहा है और कई मंत्री अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं रख पा रहे हैं। हालांकि सरकार इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताती रही है।

आर्थिक मोर्चे पर बढ़ते कर्ज को लेकर भी भाजपा लगातार सवाल उठा रही है। जयराम ठाकुर का कहना है कि मौजूदा सरकार ने साढ़े तीन साल में लगभग 45 हजार करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया है और राज्य की कुल देनदारी 1.15 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है। भाजपा पूछ रही है कि यदि इतना बड़ा कर्ज लिया गया है तो उसका असर विकास कार्यों और जनता को मिलने वाली सुविधाओं में क्यों दिखाई नहीं दे रहा।

एचआरटीसी की हालत भी अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। बसों में टायर और स्पेयर पार्ट्स की कमी, कई रूटों पर सेवाओं का प्रभावित होना, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से जुड़े मुद्दों को विपक्ष सरकार की आर्थिक स्थिति से जोड़ रहा है। भाजपा का आरोप है कि परिवहन निगम की बिगड़ती व्यवस्था का सीधा असर आम यात्रियों पर पड़ रहा है।

इसके अलावा भाजपा सरकार पर आपदा राहत, संस्थानों को बंद करने, कॉलेजों के फैसलों और विभिन्न परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर भी सवाल उठा रही है। विपक्ष इन सभी मुद्दों को जोड़कर यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि सरकार प्रशासनिक और आर्थिक दोनों मोर्चो पर दबाव में है।

यदि सरकार की चुनावी गारंटियां और घोषणाएं कागजों तक सीमित रहीं, तो भाजपा का 'वादे बनाम हकीकत' अभियान 2027 के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। ऐसे में हिमाचल की राजनीति का अगला अध्याय अब सरकार के दावों से ज्यादा उसके प्रदर्शन पर तय होगा।

क्या युवाओं के मुद्दों पर भाजपा

.....पृष्ठ 1 का शेष

अलग है। भाजपा का कहना है कि NEET मामले में जांच एजेंसियों ने कारवाई की, दोषियों की गिरफ्तारी हुई और परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए गए। अग्निवीर योजना को भाजपा सैन्य सुधार और युवाओं को नए अवसर देने वाली योजना बताती है। प्रदेश भाजपा यह भी आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस सरकार रोजगार, आर्थिक प्रबंधन और चुनावी गारंटियों को पूरा करने में असफल रही है और राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का प्रयास कर रही है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम केवल NEET पेपर लीक के विरोध तक सीमित नहीं था। यह भाजपा के खिलाफ एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की शुरुआत थी, जिसमें युवाओं का भविष्य, रोजगार, शिक्षा, सेना में भर्ती, सामाजिक सुरक्षा और केंद्र-राज्य संबंध जैसे कई मुद्दों को एक सूत्र में पिरोया गया। कांग्रेस का लक्ष्य स्पष्ट दिखता है- 2027 के चुनाव को केवल राज्य सरकार के प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की नीतियों के मूल्यांकन पर भी केंद्रित करना।

अब यह देखना होगा कि क्या युवाओं के मुद्दों पर कांग्रेस की यह आक्रामक रणनीति चुनावी समर्थन में बदलती है। इतना तय है कि हिमाचल की राजनीति में आने वाले दिनों में कांग्रेस सबसे बड़ी लड़ाई सड़कों पर नहीं, बल्कि युवाओं के भरोसे और उनके भविष्य के सवाल पर लड़ेगी।

हर मॉनसून से पहले तैयारी के दावे क्या इस बार बदलेगा सिस्टम?

शिमला/शैल। मॉनसून शुरू होने से पहले लोक निर्माण विभाग ने एक बार फिर बड़े स्तर पर तैयारियों का दावा किया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अनुसार प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से निपटने के लिए करीब 15,365 कर्मचारी जिसमें 11,137 बेलदार और 4,228 मल्टी टास्क वर्कर तथा 1,156 मशीनें तैनात की गई हैं। छह बेली ब्रिज भी तैयार रखे गए हैं और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार का कहना है कि बारिश से पहले 155.95 किलोमीटर सड़कों पर नई परत, 924.94 किलोमीटर पैचवर्क, 8,893 किलोमीटर ड्रेनेज की सफाई और 9,414 किलोमीटर कलवर्ट की सफाई पूरी कर ली गई है। अधिकारियों को 24×7 कंट्रोल रूम, अतिरिक्त निजी मशीनों की व्यवस्था और अस्पतालों, स्कूलों तथा अन्य जरूरी संस्थानों तक संपर्क बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यदि हर साल मॉनसून से पहले ऐसी व्यापक तैयारियां होती हैं, तो पहली ही भारी बारिश में सैकड़ों सड़कें बंद क्यों हो जाती हैं?

पिछले तीन वर्षो में प्रदेश ने बार-बार देखा है कि बारिश शुरू होते ही कई राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग घंटों या कई बार दिनों तक बंद रहते हैं। दूरदराज के गांवों का संपर्क टूट जाता है, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाते, पर्यटक फंस जाते हैं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या केवल मशीनों और कर्मचारियों की संख्या की नहीं, बल्कि संवेदनशील स्थानों की वैज्ञानिक पहचान, ढलानों के स्थायी उपचार, जल निकासी व्यवस्था और समय पर रखरखाव की भी है। कई स्थानों पर हर साल एक ही जगह भूस्खलन होता है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या स्थायी समाधान पर पर्याप्त काम हो रहा है।

सरकार ने इस बार अधिकारियों को भू-स्खलन संभावित क्षेत्रों की सूची तैयार करने, ड्रेनेज की नियमित सफाई, महत्वपूर्ण संस्थानों तक सड़क संपर्क बनाए रखने और नुकसान का तत्काल आकलन करने के निर्देश दिए हैं। अब इन निर्देशों की असली परीक्षा मॉनसून के दौरान होगी।

प्रदेश के लोग इस बार केवल तैयारियों के दावे नहीं, बल्कि यह देखना चाहेंगे कि क्या 15 हजार से अधिक कर्मचारियों और 1,156 मशीनों की तैनाती वास्तव में सड़कों को खुला रखने, राहत कार्यो को तेज करने और जनजीवन को सामान्य बनाए रखने में सफल होती है या फिर हर साल की तरह पहली तेज बारिश के साथ व्यवस्था की पोल खुल जाएगी।